दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 23 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 293

महत्वपूर्ण एवं खास

लोकसभा में तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। उधर आज कई महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश होने हैं। लोकसभा में शुक्रवार को विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयकों में फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 है। इसी तरह से लोकसभा में आज अंतदेर्शीय जलयान विधेयक, 2021 और अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को फिर से पेश किया जाना है।

भारतीय तटरक्षक ने एमवी कंचन के चालक दल के 12 सदस्यों को बचाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय तटरक्षक ने दिनांक 21 जुलाई, 2021 को गुजरात के उमरगाम में फंसे मोटर वेसल (एमवी) कंचन के सभी 12 चालक दल के सदस्यों को बचाया। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) मुंबई को दिनांक 21 जुलाई 2021 की दोपहर में डीजी संचार केंद्र, मुंबई से सूचना मिली थी कि खराब मौसम के बीच एमवी कंचन के ईंधन में संदूषण के कारण उसका इंजन ख़राब हो गया है जहाज़ पर और कोई विद्युत शक्ति नहीं है। बाद में शाम को जहाज के मास्टर ने सूचित किया कि एमवी कंचन,जो स्टील कॉइल को कार्गो के रूप में ले जा रहा था, का लंगर टूट गया है और स्टारबोर्ड (दाई) की ओर झुक रहा है। एमआरसीसी मुंबई ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेट (आईएनए) को सक्रिय कर दिया और एमवी हर्मीज़ को तुरंत संकट में पड़े पोत की ओर मोड़ दिया गया। समुद्र में खराब मौसमी हालात का सामना करते हुए एमवी हर्मीज ने तेजी से रात में ऑपरेशन करते हुए एमवी कंचन के चालक दल के सभी 12 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया।

वंदे भारत मिशन : कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे 61 लाख नागरिकों को वापस लाई सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। नई दिल्लीकोरोना महामारी की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को देश वापस लाने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत सरकार करीब 61 लाख नागरिकों की घर वापसी करा चुकी है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यसभा में दी। मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया है कि 30 अप्रैल 2021 तक कुल 60,92,264 भारतीयों को देश वापस लगाया गया है। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना महामारी ने चीन के बाहर पैर पसारना शुरू किया तो दुनिया के अधिकतर देशों ने सख्त लॉकडाउन और पाबंदियों की घोषणा की। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदियां लगा दी गईं। ऐसे में दुनिया के कई देशों में लाखों भारतीय फंस गए। सरकार ने इन्हें वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी और दुनिया के अलग-अलग कोनों से विशेष विमानों के जरिए लोगों को वापस लाया गया था। हालांकि, यात्रियों को इसका किराया वहन करना पड़ा था। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से 35 सौ से अधिक भारतीय नागरिकों की विदेशों में मौत हो गई।

इंडोनेशिया में मछली पकड़ने वाले जहाजों पर तूफान से 24 की मौत, 31 लापता

जकार्ता। मध्य इंडोनेशिया के पश्चिम कालीमंतन प्रांत में कुछ दिनों पहले तूफान की चपेट में आने के बाद बचाव दल को 24 शव मिले हैं और 31 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रांतीय खोज एवं बचाव कार्यालय के प्रमुख योपी हरयादी ने कहा कि घटना सांबास जिले में हुई जब दो टग बोट और मछली पकड़ने वाले जहाजों ने पहले ही तट के पास पोजीशन ले ली थी, और कुछ अन्य चरम मौसम की स्थिति की संभावना की मौसम एजेंसी की चेतावनी पर क्षेत्र की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा, मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और 31 अभी भी खोज और बचाव अभियान में हमारा लक्ष्य है। हरयादी ने कहा कि सप्ताह में दो दिन पहले इस क्षेत्र में तूफान आया था।

मुंबई में भारी बारिश से अब तक 31 मौत

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में भारी बारिश के कारण अलग-अलग घटनाओं में 31 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. दीवार गिरने और भूस्खलन के कारण ये हादसे हुए. कुछ लोगों की मौत करंट लगने से भी हुई है.देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार को भारी बारिश के कारण घर गिरने और करंट लगने की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के मुताबिक रविवार को तड़के मुंबई के विक्रोली इलाके में एक आवासीय इमारत गिर गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. इस बीच, चेंबूर के भरत नगर इलाके में भूस्खलन के कारण कुछ झोंपड़ियों पर दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई. सोमवार को भारी बारिश भारी बारिश ने मुंबई की आम जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है. सोमवार को लंबी दूरी की ट्रेनों के अलावा उपनगरीय रेल सेवा प्रभावित हुई. बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक थम गया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, अलर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे की अवधि के लिए अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने वाली कभी-कभी तेज हवाओं की भी चेतावनी दी है. रविवार को चेंबूर और विक्रोली में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम किया. बीएमसी के मुताबिक चेंबूर में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोगों की मौत विक्रोली में हुई है. दो अन्य लोगों की मौत करंट लगने और मकान ढहने के कारण हुई. बदलते मौसम से बार-बार आती तबाही पूरे भारत में मौसम कठोर होता जा रहा है और जानकार इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ कर देख रहे हैं. इस साल गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं और उत्तर के राज्यों में मानसून ने लंबा इंतजार कराया तो वहीं कुछ राज्यों में इतनी बारिश हुई कि वहां बाढ़ आ गई. तटीय शहर मुंबई हमेशा मानसून से बुरी तरह प्रभावित होती रही है और हर साल बाढ़ की शिकार भी होती है. यह आशंका है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के बदलते पैटर्न से और भी अधिक बाढ़ और क्षति हो सकती है. हाल के सालों में मानसून लंबे समय तक सूखे की ओर स्थानांतरित हो गया है और फिर अत्यधिक वर्षा के कारण अधिक आबादी वाले शहरों के डूब जाने की आशंका ज्यादा रहती है. महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कहते हैं, हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन अब यह हो रहा है. आपदा पर बयानबाजी देश की सबसे अमीर नगर निगमों में से एक बीएमसी पर हर साल मानसून के दौरान बदइंतजामी के आरोप लगते आए हैं. इस बार सप्ताहंत बारिश और उसके बाद की घटनाओं ने राजनीतिक दलों को एक बार फिर बीएमसी पर अक्षमता और कुप्रबंधन के आरोप लगाने का मौका दे दिया. आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, मानसून के दौरान फिर एक बार बीएमसी के अधिकारियों की विफलता सामने आई है. बीएमसी पर शिवसेना ही काबिज है. इस बीच महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खारघर पुलिस ने रविवार शाम दमकल अधिकारियों के साथ, एक नाले को पार कर खारघर पहाड़ियों पर गई 78 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 116 लोगों को बचा लिया है. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 23 जुलाई, 2019 को दिए जवाब में केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि 18 जुलाई 2016 से 18 जुलाई 2019 के बीच देश में भारी बारिश के साथ आने वाले तूफान, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 6,585 लोगों की मौत हुई मतलब हर साल औसतन 2,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. भारी बारिश सिर्फ आम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी प्रभावित करती है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2019 के इन तीन वर्षों में बारिश से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के कारण दो लाख से अधिक पशुधन की मौत हुई है और 39 लाख से अधिक घरों या झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा. जानकार कहते हैं कि कम समय में ज्यादा बारिश और खराब जल निकासी व्यवस्था शहरों में बार-बार बाढ़ की वजह बन रही हैं.

गुजरात तट पर फंसे मालवाहक जहाज एमवी कंचन के 12 चालक दल को बचाया गया

चेन्नई (आरएनएस)। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि गुजरात के उमरगाम में मालवाहक जहाज एमवी कंचन पर फंसे बारह भारतीय चालक दल को एक अन्य जहाज एमवी हरमीज के जरिये सुरक्षित बता लिया गया। तटरक्षक बल के अनुसार, मुंबई में इसके समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को 21 जुलाई, 2021 की दोपहर को सूचना मिली कि एमवी कंचन ईंधन संदूषण के कारण गुजरात के उमरगाम में फंसा हुआ हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसका इंजन काम नहीं कर रहा और जहाज को बिजली सप्लाई भी नहीं हो रही है। इलाके में मौसम काफी खराब था और 50 समुद्री मील तक हवाएं चल रही थीं और समुद्री लहरें 3-3.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थीं। तटरक्षक बल ने कहा कि बाद में शाम को, जहाज के मालिक ने सूचित किया कि एमवी कंचन, जो कार्गो के रूप में स्टील कॉइल ले जा रहा था, उसने लंगर गिरा दिया और स्टारबोर्ड (दाई ओर) की ओर झुकता जा रहा है। एमअरसीसी ने तब फंसे हुए जहाज एमवी कंचन की सहायता के लिए आसपास के सभी जहाजों की पहचान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जाल को सक्रिय किया। आसपास के क्षेत्र में एमवी हरमीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तुरंत संकटग्रस्त जहाज की ओर चल दिया। उबड़-खाबड़ समुद्र को पार करते हुए, एमवी हरमीज ने 21 जुलाई,2021 को रात के ऑपरेशन में एमवी कंचन के सभी 12 चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया।

जंतर मंतर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। जंतर मंतर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज विरोध-प्रदर्शन है। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा, हम वहां विस्तार से चर्चा करेंगे, हम स्पीकर भी बनाएंगे, चर्चा होगी और प्रश्नकाल भी होगा। 200 से अधिक किसान नहीं जाएंगे।

बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम बढ़ाया गया

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है, जो संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। किसान तीन विवादास्पद

कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद आयोजित करने वाले हैं। जंतर-मंतर के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

आरएएफ और सीआरएफ सहित केंद्रीय बलों के साथ दिल्ली पुलिस को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि किसानों के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है।

कोविड -19 मानदंडों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को किसानों को उचित कोविड प्रबंधन सुरक्षा के साथ जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अनुमति दी थी।

डीडीएमए की मंजूरी के अनुसार, किसानों को 22 जुलाई से 9 अगस्त तक जंतर-मंतर पर अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति होगी।

आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और दिल्ली की तीन सीमाओं- टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोविड -19 नियमों का पालन करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने निगम के लिए 1,44,200 रुपये - 2,18,200 रुपये के वेतनमान के साथ प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।

निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपये होगा और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। यह एक नया प्रतिष्ठान है। वर्तमान में, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर ऐसा कोई संगठन नहीं है। इस

स्वीकृति में रोजगार सृजन के लिए एक अंतर्निहित क्षमता है क्योंकि निगम विभिन्न प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू करेगा। निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय तथा हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा।

लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा।

निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास होगा। इसके बदले में, यह पूरे क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा।

विकास का प्रभाव बहुआयामी होगा। यह भविष्य में मानव संसाधनों के विकास और उसके बेहतर उपयोग में मदद करेगा। यह वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा और उनकी सुचारू आपूर्ति को सुगम बनाएगा। इस प्रकार, यह स्वीकृति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।

त्रिपुरा में 80 से अधिक तृणमूल कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तार

अगरतला (आरएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष आशीष लाल सिंघा सहित तृणमूल के 80 से अधिक नेताओं और कार्यकताओं को त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार कर लिया गया, जो शहीद दिवस के अवसर पर पार्टी सुप्रीमो के वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए एकजुट हुए थे। पुलिस ने कहा कि लगभग 80 तृणमूल कार्यकताओं और नेताओं को कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए उनोकोटी, उत्तरी त्रिपुरा और पश्चिम त्रिपुरा जिलों से गिरफ्तार किया गया है।

1993 में कोलकाता में तत्कालीन कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक युवा कांग्रेस रैली में पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तरी त्रिपुरा के उनोकोटी जिले के गौरनगर में तृणमूल कार्यकर्ता सबसे अधिक संख्या में एकत्र हुए थे।

हालांकि पार्टी पश्चिम बंगाल में 13 शहीदों को याद करने के लिए हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन इसने पहली बार भाजपा शासित त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न राज्यों में इस दिन को मनाया।

हालांकि, सिंघा ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें कोविड प्रतिबंध और प्रोटोकॉल बनाए रखने के बावजूद गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने आज पूसा, नई दिल्ली में पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, जिसके लिए भारतीय संसद ने दुनिया के लिए यह एक अनूठा मॉडल दिया है। इससे किसान अपनी परंपरागत किस?मों के ऊपर और किसी अन?य किस?म के अपने ही पैदा किए हुए बीज के ऊपर अधिकार प्राप?त कर सकता है। साथ ही, यह भी सुविधा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से किसानों का शोषण न हो। किसान पहले की

तरह स्वतंत्रता से खेती कर सकते हैं व पौधा प्रजनक भी अपने पूरे अधिकार का संरक्षण कर सकते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के गतिशील नेतृत्व में राष्ट्रीय आईपीआर नीति-2016, नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं व संशोधनों के जरिये लागू की गई है। जहां अन्य आईपीआर वाणिज्य मंत्रालय से सम्बद्ध है, जबकि पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) कृषि एवं किसान कल?याण मंत्रालय से सम्बद्ध है और केवल इसी आईपीआर के लिए फसलों को उगाया जाता है तथा तुलना व विश्लेषण के बाद पूरी तरह से अनुसंधान द्वारा सृजित प्रायोगिक डाटा के बाद ब्रीडर द्वारा किए गए दावे को सत्यापित करने के बाद ही प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। नई आईपीआर नीति के तहत, आईपीआर प्राधिकरणों को सरकार द्वारा आवश्यक जनशक्ति व बुनियादी ढांचा प्रदान कर मजबूत किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण के रूप में ये बड़ा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर पीपीवीएफआरए को भी सशक्त किया रहा है।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि इस भवन के बनने से प्राधिकरण के न्यायालयों की स्थापना के लिए एक मंजिल व अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ रजिस्ट्री कार्य के लिए दो मंजिलों की व्यवस्था रहेगी, जिससे आगंतुक किसानों व उपभोक्ताओं को आसानी होगी। आशा है कि नए कार्यालय भवन में अगले साल से काम होने लगेगा।

कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वसु शोभा करंदलाजे, सचिव संजय अग्रवाल, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रप्राधिकरण के सीईओ अशोक दलवई, पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष डॉ. के.वी. प्रभु, संयुक्त सचिव (बीज) अश्विनी कुमार, एएसआरबी के अध्यक्ष डॉ ए.के. मिश्रा, आईसीएआर के डीडीजी, आईएआरआई डायरेक्टर, उ.प्र. राज्य निर्माण निगम के अधिकारी, आर्किटेक्ट, निर्माण परियोजना के इंजीनियर मौजूद थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने परियोजना की जानकारी ली तथा निर्माण स्थल पर पौधारोपण भी किया।